

करबाली बेगम

बनाम

मोहम्मद सैयद और एक अन्य

7 अक्टूबर, 1980

[पी. एन. भगवती और एस. मुर्तजा फजल अली, न्यायाधिपतिगण]

यू. पी. होल्डिंग्स का समेकन अधिनियम, 1953, धारा 9 और 49- भूमि के किराए और लाभ में एक सह- भागीदार द्वारा गैर- भागीदारी- क्या बाहर किये जाने योग्य है- क्या अन्य सह- भागीदार प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त करता है।

अपीलार्थी विधवा है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उनके पति के चचेरे भाई थे। सह- भूमि दार होने के कारण विवादग्रस्त भूखंडों पर उनका संयुक्त कब्जा था। 1359 फसली तक पक्षकारों के पास एक संयुक्त खेवट था। वादी ने अपने हिस्से पर संयुक्त कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया कि वह लखनऊ में अपने बेटों के साथ रह रही थी और प्रतिवादी कृषि भूमि और उपवनों की देखभाल कर रहे थे और उसे समय- समय पर प्रतिवादी द्वारा अपना हिस्सा दिया जाता था। वह समय- समय पर गाँव भी जाती थी और अपना हिस्सा लेती थी। उसने आरोप

लगाया कि प्रतिवादियों ने उसे आश्वासन दिया कि उसके हिस्से की उचित देखभाल की जाएगी और उनके द्वारा संरक्षित किया जाएगा। वादी ने आगे आरोप लगाया कि मुकदमे से केवल 3 साल पहले ही उसे पता चला था कि उसका नाम खेवट से हटा दिया गया था, और कार्यवाही आयोजित करने के समेकन में पूरी संपत्ति को बदल दिया गया था, जिसके बारे में उसे कभी सूचित नहीं किया गया था। प्रतिवादियों ने इस आधार पर मुकदमा लड़ा कि वे विवादित भूमि पर अलग-अलग कब्जे में थे, विवादित भूखंडों पर आदिवासी का कब्जा था जिन्होंने यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत सिरदारी अधिकार हासिल किए थे, वादी ने कानून के संचालन से अपना अधिकार खो दिया, और धोखाधड़ी के आरोप से इनकार किया।

विचारण न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया लेकिन अपील पर जिला न्यायाधीश ने भूमि के दो भूखंडों के संबंध में वादी के पक्ष में संयुक्त कब्जे के मुकदमे का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की अपील स्वीकार कर ली।

अपील को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय ने, अभिनिर्धारित किया:

1. जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया, वे कानून में टिकाऊ नहीं हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रहने दिया जा सकता। [869 एफ]

2. एक और तथ्य जो स्वीकृत स्थिति से उभरता है वह यह है कि यदि प्रतिवादी 1 और 2 खेवट में वादी के साथ सह- भूमिदार थे और उनके अधीन सिरदारी किरायेदार भी थे, तो सिरदारी किरायेदार सह-भूमिका में से किसी एक सहभागीदार की भूमि पर प्रतिवादियों को अकेला छोड़ते हुये कैसे कब्जा कर सकते थे ताकि भूखंड उन्हें पुनः आवंटित किये जाये।

3. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सह- हिस्सेदार की भूमि के किराए और मुनाफे में केवल गैर- भागीदारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है, ताकि कब्जे में अन्य सह- हिस्सेदार को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व दिया जा सके। यदि इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी कानूनी स्थिति यह होगी कि प्रतिवादी नं. 1 और 2 वादी के सह- हिस्सेदार होने के नाते, वादी की ओर से रचनात्मक ट्रस्टी बन जाएंगे और वादी के अधिकार को ट्रस्टियों द्वारा संरक्षित माना जाएगा। [867 डी]

मौजूदा मामले में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों की स्थिति, रचनात्मक ट्रस्टी की प्रकृति के अलावा, कानून में वादी के कब्जे वाली होगी। [867 ई]

4.(1) जिला न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि राजस्व रिकॉर्ड से अपीलकर्ता का नाम हटाने के लिए एक योजनाबद्ध धोखाधड़ी की गई थी,

तथ्य की स्पष्ट खोज थी और भले ही यह गलत था (हालांकि यह बिल्कुल सही है) यह उच्च के लिए खुला नहीं था न्यायालय दूसरी अपील में तथ्य खोजने में हस्तक्षेप करेगा। [868 बी]

4.(ii) उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि समेकन अधिकारियों के साथ कोई धोखाधड़ी की गई थी ताकि आदेश को अमान्य बनाया जा सके। यहां उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा बनाए गए मामले को पूरी तरह से गलत समझा। [868 जी]

5. जिला न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि रिकॉर्ड पर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वादी को उपज में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, और इसलिए, यह निष्कर्ष कि वादी को कब्जे से बेदखल माना जाना चाहिए, द्वितीय अपील में बाध्यकारी था। [868 सी- डी]

6. उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड में त्रुटि की क्योंकि अपीलकर्ता का स्पष्ट साक्ष्य इस आशय का है कि उसे चकबंदी कार्यवाही के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और प्रतिवादियों द्वारा उसे आश्वासन दिया गया था कि वे उसके हिस्से की किसी भी कार्यवाही में उचित देखभाल करेंगे, जो शुरू की जायेगी। [868 एफ]

7. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब तक कानून में स्वामित्व के आधार पर किसी मुकदमे को रोकने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है,

तब तक अदालतें आसानी से पक्षकारों के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए मुकदमों की रोक का अनुमान नहीं लगा सकेंगी। [869 बी]

सूबा सिंह बनाम महेंद्र सिंह और अन्य। ए.जे.आर. 1974 एस. सी. 1657- संदर्भित किया गया।

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1204/1978

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) के द्वितीय सिविल अपील संख्या 90/75 में निर्णय एवं आदेश दिनांकित 05-04-1978 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

आर.के. गर्ग, वी.जे. फ्रांसिस और सुनील कुमार, अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादियों की ओर से उमा दत्ता, प्रेम मल्होत्रा और किशन दत्त, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय फजल अली, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

कैसे बेईमान चचेरे भाई, उनके भाई की विधवा की भूमि की देखभाल कर रहे हैं, जो कि उस स्थान से बहुत दूर स्थित है जहां विधवा रह रही थी, उनकी विधवा भाभी द्वारा उन पर जताये गये विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हुये और ईमानदारी से संपत्ति का प्रबंधन करने और उसे हिस्सा देने की एक गुलाबी तस्वीर चित्रित करने के बाद, उन्होंने अपनी भाभी के हिस्से पर लालची नजरें डालीं और एक घृणित चित्रण के साथ, उसे वंचित करने की कोशिश की। उसके कानूनी हिस्से को छीनना और

उसके कानूनी अधिकारों से वंचित करना हमारे ग्रामीण जीवन की कोई असामान्य विशेषता नहीं है। यह इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है, जहां भाभी को परिस्थितियों के बल पर लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था ताकि उसके चचेरे भाइयों के हाथ संपत्ति के अपने हिस्से को छीनने के अपने कानूनी अधिकारों को साबित किया जा सके। यह गरीब और असहाय अपीलकर्ता, करबलाई बेगम की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से न्याय पाने में विफल रही, उसे देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसलिए, विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद उसने वर्तमान अपील इस न्यायालय में दायर की है।

मामले के तथ्यों को समझने के लिए, पक्षों की एक संक्षिप्त वंशावली देना आवश्यक हो सकता है जो जिला न्यायाधीश के फैसले में पाई जाएगी और नीचे दी गई है:

मीर तफज्जुल हुसैन

|

सैयद खादिन हुसैन

सैयद सादिक हुसैन

|

|

|

सैयद लाक हुसैन

मो. बशीर (प्रति.नं.1)

मो. रशीद

(विधवा करबलाई बेगम- वादी)

(विधवा श्रीमती शकीरा बानो, प्रति.नं.2)

अपीलकर्ता करबलाई बेगम सैयद लाक हुसैन की विधवा थीं और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 उनके पति के चचेरे भाई थे। स्वीकृत स्थिति यह प्रतीत होती है कि वादी और प्रतिवादी सह- भूमिदार होने के कारण विवादित भूखंडों के संयुक्त कब्जे में थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 द्वारा जमींदारी के उन्मूलन के बाद वादी- अपीलकर्ता, मो. बशीर और मो. रशीद विवादित भूखंडों का भूमिदार बन गया। यह भी विवादित नहीं है कि 1359 फसली तक दोनों पक्षों का एक संयुक्त खेवट था, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत खेवट के उद्धरण से प्रतीत होता है। वादी का मामला यह था कि वह अपने बेटों के साथ लखनऊ में रह रही थी और 'उसके पति के चचेरे भाई उस जमीन की देखभाल कर रहे थे जिसमें कृषि भूमि और उपवनों शामिल थी और उसे समय- समय पर उसके चचेरे भाइयों द्वारा उसका हिस्सा दिया जाता था। यह भी आरोप लगाया कि वह समय- समय पर गांव जाकर अपना हिस्सा लेती थी। विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी, मो. बशीर और मो. रशीद उन संपत्तियों का प्रबंधन करता था जो संयुक्त थीं और उसे अपना हिस्सा देता था और उसे आश्वासन देता था कि उसके हिस्से की वे उचित देखभाल और सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार, वादी का विश्वास हासिल करने के बाद पहले और दूसरे प्रतिवादियों ने संपत्तियों का प्रबंधन करना जारी रखा और उसे अपना हिस्सा दे दिया ताकि उसे उनके बुरे इरादों पर संदेह न हो। वादी ने

अपने बयान में आगे आरोप लगाया कि चकबंदी की कार्यवाही के दौरान, अलग-अलग भूखंडों को उकेरा गया था और उसे प्रतिवादियों द्वारा किसी भी कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया था और उसे लगा कि उसके हिस्से की उचित देखभाल की जा रही है। मुकदमे से केवल तीन साल पहले वादी को पता चला कि उसका नाम खेवट से हटा दिया गया था और पूरी संपत्ति प्रतिवादियों के नाम पर कार्यवाही आयोजित करने के समेकन में बदल दी गई थी। इसलिए, वादी द्वारा शेयर पर संयुक्त कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया।

मुकदमे को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था, लेकिन अपील पर, जिला न्यायाधीश ने केवल चकबंदी भूखंड संख्या 201 और 274 के संबंध में संयुक्त कब्जे के मुकदमे का फैसला सुनाया। प्लॉट नंबर 93, 94 और 106 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा वादी के मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा गया था। इसलिए, वर्तमान मामले में, हम केवल चकबंदी प्लॉट नंबर 201 और 274 से चिंतित हैं। प्लॉट नंबर 201 प्लॉट नंबर 158, 159, 164, 165, 167, 166, 168, आदि से बनाया गया था और प्लॉट नंबर 274 का निर्माण प्लॉट संख्या 267, 268, 272, 273, 276, 277, 273, 279 और 280 से किया गया था।

मुकदमे का प्रतिवादियों द्वारा मुख्य रूप से ज़मीनी आधार पर विरोध किया गया कि प्रतिवादी विवादित भूमि या भूखंडों पर अलग-अलग

कब्जे में थे और वादी को उनसे कोई सरोकार नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि कुछ समय पहले, विवाद में भूमि संयुक्त थी, लेकिन समेकन कार्यवाही के दौरान वादी के कब्जे वाले भूखंडों पर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के तहत सरदार के अधिकार हासिल कर लिए थे। अधिनियम, 1950, कानून के संचालन से वादी ने अपना स्वामित्व खो दिया। वादी का यह आरोप कि प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी की है, दृढ़ता से इनकार किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के आरोपों को स्वीकार कर लिया और वादी के मामले को खारिज कर दिया। हालाँकि, जिला जज ने स्वीकार किये गये तथ्यों पर जमींदारी उन्मूलन के बाद भी स्थिति को सही पाया। यह था कि 1357 फसली में वादी का नाम स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों के साथ सह- हिस्सेदार के रूप में दर्ज किया गया था और 1359 फसली तक ऐसा ही जारी रहा जैसा कि प्रदर्श- 2 से प्रकट होता है। विद्वान जिला न्यायाधीश ने आगे पाया कि वादी का नाम 1359 फसली के बाद अचानक हटा दिया गया था और उन परिस्थितियों को दिखाने के लिए किसी न्यायिक कार्यवाही थी जिसके तहत वादी का नाम सह- भूमिदार के तौर पर हटा दिया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश, दस्तावेजी साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोहम्मद बशीर, और मो. रशीद द्वारा किसी प्रकार की

धोखाधड़ी की गई होगी जब 1362 फसली में भूखंडों को विशेष रूप से मोहम्मद बशीर और मो. रशीद के नाम पर दर्ज किया था। भले ही प्रतिवादी द्वारा वादी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, क्योंकि प्रतिवादी सह- हिस्सेदार थे, जब तक कि स्पष्ट रूप से बेदखल करने का अनुरोध नहीं किया गया था या सह- हिस्सेदार के रूप में प्रतिवादियों के कब्जे को साबित नहीं किया गया था, कानून में वादी का कब्जा माना जाएगा।

एक और स्पष्ट तथ्य जो स्वीकृत स्थिति से उभरता है वह यह है कि यदि मो. बशीर और मो. रशीद खेवट में वादी के साथ सह- भूमिदार थे और उनके अधीन सिरदारी किरायेदार भी थे, सिरदारी किरायेदार प्रतिवादियों को अकेला छोड़कर सह- हिस्सेदारों में से एक की भूमि पर कैसे कब्जा कर सकते थे ताकि भूखंड उन्हें फिर से आवंटित कर दिए जाएं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सह- हिस्सेदार की भूमि के किराए और मुनाफे में केवल गैर- भागीदारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है, ताकि कब्जे में दूसरे सह- हिस्सेदार को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व दिया जा सके। वास्तव में यदि इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी कानूनी स्थिति यह होगी कि मो. बशीर और मो. रशीद, वादी के सह- हिस्सेदार होने के नाते, वादी की ओर से रचनात्मक ट्रस्टी बन जाएगा और वादी के अधिकार को ट्रस्टियों द्वारा संरक्षित माना जाएगा। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील कानून की इस स्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ थे। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों का

कब्ज़ा, रचनात्मक ट्रस्टी की प्रकृति के अलावा, कानून में वादी का कब्ज़ा होगा।

इसके अलावा, तथ्य यह है कि साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जिला न्यायाधीश इस तथ्य के स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चकबंदी कार्रवाई के दौरान प्रतिवादियों या किसी अन्य द्वारा स्पष्ट धोखाधड़ी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वादी के अधिकारों को समाप्त करने की मांग की गई। इस संबंध में विद्वान जिला न्यायाधीश ने निम्नलिखित पाया:-

"इससे पता चलता है कि अपीलकर्ता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने के लिए एक योजनाबद्ध धोखाधड़ी की गई थी और उत्तरदाताओं द्वारा गांव में चकबंदी कार्यों का पूरा फायदा उठाया गया था। लिखित बहस के कागज 31 ए के पैरा 20 में, यह उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया है कि उन्होंने मुकदमे के माध्यम से वाद भूमि को हासिल किया है और चकबंदी कार्यवाही के दौरान वादी का अधिकार समाप्त हो गया है। मेरे सामने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उप-किरायेदारों और प्रतिवादियों ने विशेष रूप से भूखंडों का अधिग्रहण किया। यहां तक कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है या तर्कों के माध्यम से मुकदमेबाजी के माध्यम से

भूखंड प्राप्त हो जाते हैं, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि वादी के अधिकार समाप्त हो गए।"

विद्वान जिला न्यायाधीश का यह निष्कर्ष तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष था और भले ही यह गलत था (हालाँकि हमारी राय में यह बिल्कुल सही है) यह दूसरी अपील में तथ्य के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था। इसके अलावा, जिला न्यायाधीश ने एक अन्य स्थान पर पाया कि रिकॉर्ड पर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वादी को उपज में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया था और इसलिए, निष्कर्ष यह था कि वादी को कब्जे से बेदखल माना जाना सही नहीं था। इस संबंध में विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"प्रतिवादियों के वकील द्वारा दिया गया तर्क कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि वादी को उपज में से कोई हिस्सा दिया गया था और इसलिए, वादी को कब्जे से बेदखल माना जाना चाहिए, भ्रामक है।"

यह भी तथ्य की खोज थी- जो दूसरी अपील में बाध्यकारी थी। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वादी को यूपी जोत समेकन अधिनियम, 1953 की धारा 9 के तहत याचिका दायर करने से रोका गया

था या कि प्रतिवादियों ने वादी को आश्वासन दिया कि उसका नाम समेकन कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यहां भी, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड में त्रुटि की क्योंकि पीडब्लू, करबलाई बेगम के स्पष्ट साक्ष्य इस आशय के हैं कि उन्हें चकबंदी कार्यवाही के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और प्रतिवादियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे शुरू की जाने वाली किसी भी कार्यवाही में उसके हिस्से की उचित देखभाल करेंगे। इसे जिला न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि समेकन अधिकारियों के साथ कोई धोखाधड़ी की गई थी ताकि आदेश को अमान्य बनाया जा सके। यहां उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा बनाए गए मामले को पूरी तरह से गलत समझा। वादी के मामले में ऐसा कभी नहीं था कि चकबंदी प्राधिकारियों के साथ कोई धोखाधड़ी की गई हो। उसने अपनी शिकायत और साक्ष्य में जो कहा था, वह यह था कि प्रतिवादियों ने उसे यह आश्वासन देकर धोखाधड़ी की थी कि उसके हिस्से की उचित देखभाल की जाएगी और इस स्पष्ट समझ पर उसने प्रतिवादियों पर संपत्तियों का पूरा प्रबंधन छोड़ दिया था, जो उनका प्रबंधन भी करते थे। विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा रखे गये प्रकरण के इस हिस्से की पूरी तरह से सराहना नहीं की और जिला जज ने इसे स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लिया। इसलिए, इन परिस्थितियों में, चकबंदी कार्यवाही में की

गई धोखाधड़ी के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कानूनी रूप से सही नहीं था।

अंतिम आधार जिस पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को गैर-अनुकूलित किया, वह यह था कि चकबन्दी पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश जोत समेकन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत वाद उक्त अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत प्रतिबंधित था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब तक स्वामित्व के आधार पर किसी मुकदमे को रोकने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तब तक अदालतें आसानी से पक्षकारों के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए मुकदमे की रोक का अनुमान नहीं लगा सकेंगी। सुभा सिंह बनाम महेंद्र सिंह और अन्य में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-

"इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट था कि धारा 23 के तहत योजना को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने के बाद, कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने पर विरासत के आधार पर उत्परिवर्तन के लिए एक आवेदन, ऐसा मामला नहीं है जिसके संबंध में एक आवेदन दायर किया जा सकता है" इस अधिनियम के प्रावधान" धारा 49 के खंड 2 के अर्थ के भीतर हैं। इस प्रकार, धारा 49 का अन्य अंग भी आकर्षित नहीं होता है। इसका परिणाम यह है कि सिविल अदालतों के

जांच और निर्णय के अधिकार क्षेत्र पर रोक की दलील दी गई है- भूमि के स्वामित्व या वादी के पुत्रत्व पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है।"

ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह मानकर कानूनन गलती की कि वर्तमान मुकदमा उत्तर प्रदेश जोत समेकन अधिनियम, 1953 की धारा 49 के द्वारा वर्जित था।

इस प्रकार, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया, वे कानून में टिकाऊ नहीं हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रहने दिया जा सकता।

इसलिए, हम सभी लागतों के साथ अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं, जहां तक प्लोट नंबर 201 और 274 का संबंध है, संयुक्त कब्जे के लिए वादी के मुकदमे को डिक्री करते हैं और जिला न्यायाधीश के फैसले को बहाल करते हैं। इस न्यायालय द्वारा अनुमत लागत उत्तरदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय में जमा की गई और अपीलकर्ता को भुगतान की गई रुपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र) की राशि के विरुद्ध समायोजित की जाएगी और शेष राशि उत्तरदाताओं को वापस की जा सकती है।

एन.के.ए.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।